

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	कार्तिक 10, सोमवार, शाके 1943-नवम्बर 01, 2021 <i>Kartika 10, Monday, Saka 1943- November 01, 2021</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**वित्त(जीएण्डटी) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, नवम्बर 1, 2021**

**जी.एस.आर.275.**— राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 15-04-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,  
संयुक्त शासन सचिव।

**वित्त (जी एण्ड टी) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, 15 अप्रैल, 2021**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, सामान्य शर्तों की विद्यमान शर्त 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“4. यदि, माल, संकर्म का उपापन, सरकारी कंपनी या केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केंद्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां, जो राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित से भिन्न हैं, से किया जाना है, तब उपापन से पूर्व विभागीय उच्च अधिकार समिति का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा। विभागीय उच्च अधिकार समिति निम्नानुसार होगी:-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव | - अध्यक्ष    |
| 2. विभागाध्यक्ष                                  | - सदस्य      |
| 3. लेखा सेवाओं का वरिष्ठतम अधिकारी               | - सदस्य      |
| 4. तकनीकी अधिकारी (यदि अपेक्षित हो)              | - सदस्य      |
| 5. भण्डार का प्रभारी अधिकारी                     | - सदस्य-सचिव |

टिप्पण: विभागीय उच्च अधिकार समिति की बैठक तब तक नहीं होगी जब तक कि लेखा सदस्य उपस्थित न हो।

विभागीय उच्च अधिकार समिति का सदस्य-सचिव निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,-

- (i) बैठक का कार्यसूची टिप्पण और कार्यवृत्त तैयार करना;
- (ii) माल के प्रदाय/संकर्म के निष्पादन के लिए यदि राजस्थान राज्य के सरकारी संगठन/सरकारी कंपनियां/बोर्ड/निगम/सहकारी सोसाइटियां इत्यादि समर्थ हों तब भी राज्य के बाहर से उपापन का न्यायोचित्य;
- (iii) राजस्थान के बाहर और राज्य के भीतर से उपापन की विषय-वस्तु की दरों के तुलनात्मक विवरण तैयार करना; और
- (iv) उपापन की विषय-वस्तु की दरों के मद-वार ब्यौरे तैयार करना।

[सं.एफ. 2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. पृथ्वी,

शासन सचिव।

वित्त (बजट) विभाग।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।